गैर-विकास व्यय की वार्षिक दर में निरन्तर वृद्धि हो रही हैं;

(ख)यदि हां, तो क्या यह सच है कि जो व्यय दर 1985- 90 के दौरान 18.2 प्रतिशत और 1999-95 के दौरान 20.9 प्रतिशत थी वह 1998-99 के दौरान बढ़कर 32.8 प्रतिशत हो गई हैं; और

(ग)यदि नहीं, तो गैर-विकास व्यय में वार्षिक वृद्धि के संबंध में सरकार का आकलन क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत एक अध्ययन "फाइनेंसेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट 1998-99" (राज्य सरकारों की वित्त व्यवस्था 1998-99) में राज्यों के गैर विकास खर्चो में हो रही लगातार वृद्धि संबंधी तथ्यों को दर्शाया गया हैं।

Hike in Customs Duty on Gold

*13. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have recently increased customs duty on gold import and if so, the details thereof and the reasons therefor:

(b) whether Government are aware that as a result of the increase in the customs duty on gold, Dubai gold trade would immensely benefit as N.R.Is. will buy more jewellery to carry home as gold in India has become more expensive; and

(c) if so, what is Government's reaction in regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARTHANAN): (a) Yes Sir, the government have increased the rate of duty on gold import from Rs. 250 per 10 gms. to Rs. 400 per 10 gms. with effect from 5.1.99 vide notification No. 2/99-Cus. dated 4.1.99. It was considered appropriate to increase the duty in order to moderate the abnormally high quantum of imports and also to garner additional revenue to the extent possible.

(b) and (c) The rate of duty on gold and gold jewellery is identical. Government does not apprehend any harm to the finances of the country as a result of the increase of import duty on gold.

जीवन बीमा निगम के हजारीबाग डिवीजन में सहायक के पदों के लिए रिक्तियां

*14 **श्री राजनाथ सिंह** :
श्रीमती मालती शर्मा :

क्या वित्त मंत्री 15 दिसम्बर, 1998 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1738 के दिए उत्तर को देखेंगे ओर यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)जीवन बीमा निगम, हजारीबाग डिवीजन, बिहार में 157 सहायकों की नियुक्ति के लिए तीन वर्ष पूर्व बनाए गए पैनल के लिए कब तक पदरिक्त होने की संभवाना हैं;

(ख)क्या यह सच है कि इस डिवीजन में अनेक पद रिक्त हैं जिन्हें भरा जाना है लेकिन इसके बावजूद प्रबंधक द्वारा नियुक्तियों में विलम्ब किया जा रहा हैं;

(ग)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ)सरकार द्वारा अब तक हजारीबाग डिवीजन में कितनी रिक्तियां चिन्हित की गई हैं और इन 157 सहायकों को कब तक नियुक्त कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम0आ0 जर्नादनन) : (क) बदलती हुई व्यसायगत आवश्यकताओं के अनुसार, जीवन बीमा निगम कर्मचारियों की स्थिति के पैटर्न का पुनरीक्षण कर रहा है और नए कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहा हैं। इसलिए ठीक-ठीक यह बताना सम्भव नहीं है कि इस पैनल के लिए कब तक रिक्तियां निलेंगी।

(ख)जी, नहीं।

(ग)प्रश्न नहीं उठता।

(घ)जीवन बीमा निगम किसी विशेष अवधि के लिए रिक्तियों को चिन्हित करने की प्रणाली का अनुपालन नहीं करता जो पनैल तैयार किया गया है उसके लिए कोई समय सीमा नहीं हैं और जब कभी भी रिक्तियां होंगी तभी उन्हें भरा जाएगा।

कर विवाद समाधान योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र

*15. **श्री राघवजी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)31 जनवरी, 1999 को समाप्त हुई कर विवाद समाधान योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या कितनी हैं;

(ख)इप आवेदनों से 31 मार्च, 1999 तक कुल कितनी राशि जमा होने की संभावना हैं; और

(ग)देश के ऐसे प्रथम दस स्थान कौन-कौन से हैं जहां से सर्वाधिक धनराशि जमा होने की संभावना हैं?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम0आर0 जनार्दनन) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31.1.99 को समाप्त हुई "कर विवाद समाधान योजना" के अंतर्गत, 31.1.99 तक प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष करों के संबंध में प्राप्त घोषणाओं की कुल संख्या क्रमशः 48041 और 18547 हैं।

दायर की गई घोषणाओं में देय कर कर निर्धारण अभिहित प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा और यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ हैं। इस योजना के अंतर्गत इन घोषणाओं के जरिए 31.3.99 तक प्रत्यक्ष करों के संबंध में 950 करोड़ रूपए और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में 850 करोड़ रूपए की अनुमानित राशि प्राप्त होने की संभावना हैं।

पहले दस क्षेत्र/जोन जहां सबसे अधिक संख्या में घोषणाएं दायर की गई है और जहां से अधिकतम राशि प्राप्त होने की संभावना हैं, का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

प्रत्यक्ष दर

क्षेत्र जहां से अधिकतम घोषणाएं प्राप्त हुई।		क्षेत्र जहां से अधिकतम राशि प्राप्त होने की संभावना हैं।	
क्रं. सं.	क्षेत्र	क्रं. सं.	क्षेत्र
1.	मुम्बई	1.	मुम्बई
2.	अहमदाबाद	2.	नई दिल्ली
3.	नई दिल्ली	3.	चेन्नई
4.	कलकत्ता	4.	कलकत्ता
5.	कानपुर	5.	अहमदाबाद
6.	पुणे	6.	बैंगलूर
7.	चेन्नई	7.	जयपुर
8.	भोपाल	8.	पुणे
9.	पटना	9.	कानपुर
10.	बैंलूर	10.	हैदराबाद

अप्रत्यक्ष कर

वे जोन जहां से अधिकतम घोषणाएं प्राप्त हुई।		वे जोन जहां से अधिकतम राशि प्राप्त होने की संभावना हैं।	
क्रं.सं.	क्षेत्र	क्रं. सं.	क्षेत्र
1.	मुम्बई	1.	मुम्बई
2.	बड़ोदरा	2.	बैंगलूर
3.	दिल्ली	3.	बड़ोदरा
4.	पुणे	4.	कलकत्ता
5.	कानपुर	5.	चेन्नई
6.	चेन्नई	6.	दिल्ली
7.	बैंगलूर	7.	पुणे
8.	जयपुर	8.	कानपुर
9.	कलकत्ता	9.	हैदराबाद
10.	हैदराबाद	10.	जयपुर

Fall out of Increase in Import Duty on Gold

*16. SHRI GHUFRAN AZAM:

SHRI ABANI ROY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have recently increased the import duty on gold;

(b) if so, the reasons therefor and justification thereof;

(c) whether such steps of Government would not encourage smuggling; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARTHANAN): (a) and (b) Yes Sir, the Government have increased the rate of duty on import of gold from Rs. 250 per 10 grams to Rs. 400 per 10 grams with effect from 5.1.99 vide notification No. 2/99-Cus. dated 4.1.99. It was considered appropriate to increase the duty in order to moderate the abnormally high quantum of